IFAD
Enabling poor rural people to overcome poverty
उत्तराखण्ड शासन

एकीकृत आजीविका संवाद

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति– एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना
उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी

अंक 1 सितम्बर, 2014

संदेश

अन्तरराष्ट्रीय कृषि विकास निधि (IFAD) व उत्तराखण्ड सरकार द्वारा वित्त पोषित "एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना (Integrated Livelihood Support Project-ILSP)" का क्रियान्वयन राज्य के 11 पर्वतीय जनपदों के 41 विकासखण्डों में किया जा रहा है। परियोजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2017-18 तक की अवधि के लिए स्वीकृत है, जिसका क्रियान्वयन 01 जुलाई 2013 से प्रारम्भ हुआ है।

परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में गरीबी को कम करना है। ग्रामीण परिवारों को चिरन्तर आजीविका के अवसर उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाते हुये, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर इस उद्देश्य की प्राप्ति की जानी है।

पर्वतीय जनपदों में आजीविका संवर्धन हेतु परियोजना की रणनीति एक द्विआयामी दृष्टिकोण अपनाने की है। 1. अधिकांश परिवारों हेतु खाद्य प्रणाली विकसित करने में सहयोग करना। 2. गैर कृषि गतिविधि सहयोग, विशेष रूप से ग्रामीण पर्यटन क्षेत्र में समुदाय की भागीदारी तथा व्यावसायिक प्रशिक्षण के माध्यम से नगद आय अर्जन पर परियोजना का मुख्य जोर है।

परियोजना का कार्यान्वयन तीन संस्थाओं- उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति-UGVS, परियोजना समिति जलागम प्रबन्ध निदेशालय-PSWMD तथा उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्द्धन कम्पनी-UPASaC के द्वारा किया जा रहा है।

परियोजना की बहुआयामी गतिविधियों के मद्देनजर, परियोजना की गतिविधियों को दर्शाने हेतु, एक त्रैमासिक न्यूज लैटर प्रकाशित किया जा रहा है। न्यूज लेटर में परियोजना की नवीन पहलों एवं प्रयासों को केस अध्ययनों के रूप में दिया जा रहा है।

बुलेटिन का पहला अंक अवलोकनार्थ आपके हाथों में है। इसके लिये मैं अपनी परियोजना के सहयोगियों को उनके प्रयास के लिये बधाई देता हूं। इस बुलेटिन में सुधार लाने के लिये, हमारे सुधी पाठकों के सुझावों का हमेशा स्वागत रहेगा।

अपर मुख्य सचिव/FRDC
उत्तराखण्ड शासन तथा अध्यक्ष MC, UGVS
एवं अध्यक्ष, PMC, ILSP

स्वायत्त सहकारिता एवं जिला प्रशासन के मध्य समन्वयन का नवीन प्रयास

चेतना स्वायत्त सहकारिता (SRC), सिरसौड़ा, जनपद अल्मोड़ा के विकासखण्ड लमगड़ा में वर्ष 2007 से 18 राजस्व ग्रामों में 71 स्वयं सहायता समूहों के साथ कार्य कर रही है। सहकारिता से 382 सदस्य जुड़े हैं। चेतना SRC को 'एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना' (ILSP) द्वारा सहयोग किया जा रहा है।

सहकारिता कृषि उत्पादन बढ़ाने हेतु अपने सदस्यों को बीज, खाद, कीटनाशक दवाएं, पशु पोषक आहार आदि उपलब्ध करा रही है। सहकारिता स्थानीय समुदाय को दैनिक उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध कराने व लघु उद्यमों को बढ़ावा देने हेतु प्रशिक्षण आदि प्रदान कर रही है साथ ही सदस्यों को चहुंमुखी लाभ पहुंचाने व स्थानीय उत्पादों हेतु उचित बाजार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों के साथ अभिसरण कर विभिन्न योजनाओं के माध्यम से लाभान्वित करने हेतु प्रयास कर रही है। सहकारिता ने इस कड़ी में समेकित बाल विकास परियोजना (ICDS) के आंगनबाड़ी केन्द्रों को 'टेक होम राशन' उपलब्ध करवाकर जहां एक ओर समुदाय को गुणवत्ता युक्त आहार उपलब्ध करवाने का प्रयास किया, वहीं दूसरी ओर अपने लिए एक सतत् व्यापारिक गतिविधि को भी तलाशा है।

खाद्य सामाग्री की आपूर्ति हेतु ICDS एवं सहकारिता के मध्य बैठक

सहकारिता की इस अभिनव पहल एवं जोश को देखते हुए प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा ने मुख्य विकास अधिकारी, अल्मोड़ा की अध्यक्षता में सहकारिता प्रतिनिधि, ICDS के जिला परियोजना व सहायक परियोजना अधिकारी की माह जनवरी 2014 में एक बैठक आयोजित करवाई। जिसमें ICDS द्वारा आंगनबाड़ी केन्द्रों को वितरित किये जाने वाले पुष्टाहार को ILSP द्वारा समर्थित सहकारिताओं के माध्यम से आपूर्ति किये जाने पर सहमति बनी।

सहकारिता ने आंगनबाड़ी केन्द्रों को आवश्यक समस्त टेक होम राशन उपलब्ध करवाने संबंधी ICDS के साथ समस्त औपचारिकताएं पूर्ण कर उत्पादों के सैम्पल उपलब्ध कराये। ICDS अधिकारी द्वारा सहकारिता उत्पादों के सैम्पल की जांच के उपरान्त माह फरवरी 2014 के लिए आवश्यक टेक होम राशन की आपूर्ति हेतु निर्देशित किया गया। सहकारिता ने कुल 787 गर्भवती महिलाओं एवं 978 बच्चों के लिए टेक होम राशन उपलब्ध कराया। इस गतिविधि से सहकारिता का मार्च 2014 तक कुल ₹ 216325/- का टर्नओवर हुआ।

सहकारिता एवं सरकार के संयुक्त प्रयास का प्रभाव प्रत्यक्षतः देखने को मिला है। सामग्री की गुणवत्ता एवं पौष्टिकता के विषय में समूह चर्चा तथा व्यक्तिगत् साक्षात्कार से ज्ञात हुआ कि केन्द्रों को उपलब्ध करवायी गयी सामग्री की पैकिंग, वजन एवं पौष्टिकता आदि पूर्व में अन्य स्रोतों की सामग्री से बेहतर है।

अल्मोड़ा जनपद के जिला प्रशासन, ILSP परियोजना, चेतना सहकारिता व समेकित बाल विकास परियोजना के संयुक्त प्रयासों से आरम्भ किया गया, उपरोक्त नवीन प्रयास, न सिर्फ संबंधित विभागों बल्कि वास्तविक लाभार्थियों द्वारा भी काफी सराहा गया है।

सहकारिता द्वारा आंगनवाड़ी केन्द्रों को खाद्य सामग्री की सप्लाई

परियोजनान्तर्गत युवक/युवतियों को रोजगारपरक व्यावसायिक प्रशिक्षण

परियोजनान्तर्गत परियोजना क्षेत्र के युवक/युवतियों को रोजगारपरक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान करने के लिए आठ ट्रेडस- हॉस्पिटैलिटी, कम्प्यूटर आधारित एकाउटिंग एवं ERP Solution, डाटा इन्ट्री ऑपरेटर, कम्प्यूटर हार्डवेयर मैकेनिक, मोबाईल रिपेयरिंग, ब्यूटी हैल्थ मैनेजमैंट, रिटेलिंग, हॉस्पिटल एवं नर्सिंगहोम असिस्टैंट को चिन्हित किया गया है।

पायलट के रूप में 695 युवक/युवतियों को उपरोक्त ट्रेडस में प्रशिक्षण प्रदान कराने हेतु संस्थाओं- IL&FS- Delhi, IACM- Delhi, Gras Education- Delhi, G&G- Panchkula एवं दिव्य प्रेम सेवा मिशन, हरिद्वार को चिन्हित किया गया है। जून 2014 तक कुल 191 युवक/युवतियों को उपरोक्त ट्रेडस में प्रशिक्षण दिलाया गया तथा कुल 81 युवक/युवतियों को रोजगार हेतु प्रस्ताव मिल चुका है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के 125 छात्र/छात्रओं को 6 माह/12 माह के रोजगारपरक पाठ्यक्रमों में परियोजना के व्यय पर प्रवेश दिलाया गया है।

परियोजना में ज्ञान प्रबन्धन

परियोजना के क्रियान्वयन में अनुश्रवण एवं ज्ञान प्रबन्धन एक महत्वपूर्ण घटक होता है। परियोजना की गतिविधियों के अनुश्रवण हेतु परियोजना का Management Information System (MIS) विकसित किया गया है, जिससे System Generated Report प्राप्त की जा रही है। MIS से वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट, उर्पाजन योजना, परियोजना प्रगति का अनुश्रवण किया जाता है। उक्त रिपोर्ट राज्य, जनपद व ब्लॉक स्तर पर आवश्यकतानुसार देखी जा सकती है। ज्ञान प्रबन्धन के अन्तर्गत निम्न पहल की जा रही है-

क्रियान्वयन के दौरान संस्थागत एवं स्टाफ स्तर पर अर्जित किये जा रहे ज्ञान को संस्थान की धरोहर के रूप में संजोने व उसे आवश्यकतानुसार उपयोग में लाने हेतु एक Online Resource Center बनाया गया है। परियोजना कार्यालय/स्टाफ के मध्य जानकारी का प्रसार करने हेतु इसका उपयोग किया जा रहा है।

परियोजना स्टाफ, फेडरेशन के बोर्ड सदस्य एवं चयनित लाभार्थियों को उपयोगी जानकारी Voice & Text संदेश के रूप में प्रसारित की जाती है।

GIZ के सहयोग से m-Gramin कार्यक्रम के अन्तर्गत 550 प्रगतिशील किसानों को कृषि, बाजार, मौसम आदि की जानकारी Text संदेश के रूप में प्रसारित की जा रही है।

परियोजना के इस कार्य को IFAD की अन्तरराष्ट्रीय कार्यशाला में तथा IFAD Supervision Mission द्वारा सराहा गया है।

आजीविका वित्त पोषण

परियोजना के वित्तीय विकास (Development financing) घटक के अन्तर्गत वर्ष 2014-15 में परियोजना जनपदों के 133 समूहों (SHG) द्वारा ₹ 57.70 लाख की नकद साख सीमा (CCL) बनाई गई है, इसको बीज क्रय, पशुधन क्रय, मकान रिपेयरिंग एवं निर्माण तथा अन्य आवश्यकताओं में उपयोग किया जा रहा है। कार्यक्षेत्र में सूक्ष्म व लघु उद्यमों- सूक्ष्म डेयरी, जनरल स्टोर, टेंट हाउस, वाहन आदि हेतु ₹ 67.87 लाख की धनराशि के 71 टर्मलोन एवं 318 किसानों द्वारा ₹ 120 लाख के किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) बनाए गये हैं।

उत्तराखण्ड पर्वतीय आजीविका संवर्धन कम्पनी द्वारा वर्ष 2012 में सोशल वेंचर केपिटल फण्ड (SVCF) के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में उद्यमों को प्रोत्साहित करने के क्रम में उत्तराखण्ड ग्रामीण बैंक-बागेश्वर, अल्मोड़ा जिला सहकारी बैंक एवं टिहरी जिला सहकारी बैंक के साथ मिलकर 42 उद्यमों हेतु ₹1.12 करोड़ की धनराशि ऋण के रूप में स्वीकृत की गई जिसमें बैंकों द्वारा ₹56.39 लाख एवं उपासक द्वारा ₹55.99 लाख वित्त पोषण किया गया। उक्त गतिविधि से ₹40.66 लाख का ऋण उद्यमियों द्वारा वापस जमा किया जा चुका है।

मुख्य आकर्षण

परियोजनान्तर्गत गठित देव महिमा उत्पादक समूह, ध्याड़ी, अल्मोड़ा, हैण्डलूम का कार्य करता है। यह समूह नारी एकता स्वायत्ता सहकारिता, जनपद अल्मोड़ा से सम्बद्ध है। समूह को मई 2014 में Village Ways Charitble Trust, New Delhi से 1,000 शॉल का आर्डर मिला है। आर्डर के साथ अग्रिम धनराशि के रूप में ₹ 50,000/- भी प्राप्त हुई है। समूह द्वारा समय पर आर्डर की आपूर्ति की गई। Village Ways ने समूह को उनके प्रयास एवं गुणवत्तापरक शॉल की आपूर्ति के सम्बन्ध में प्रशंसा पत्र भेजा है-

Villageways Charitable Trust
Creating capacity for financial self sufficiency in remote rural communities, New Delhi

Dear Sir,

On behalf of Village Ways Charitable Trust, we wish to send you a letter of thanks and appreciation for a commendable job of work very well executed. The quality and execution of the order was seamless.

Thank you for your co operation and communication between the Trust and Nari Ekta Swayatt Sahakarita Jamraadi.

we look forward to supporting your organization in future.

Ratnamala Kapur
Managing Trustee
Village Ways Charitable Trust

सीधे उपभोक्ता तक

जनपद बागेश्वर की सहकारिताओं ने परियोजना के सहयोग से स्थानीय उत्पाद एवं उत्पाद से तैयार सामग्री को किसान से सीधा उपभोक्ता तक पहुंचाने की रणनीति तय की। इस हेतु मुख्य विकास अधिकारी ने विकासभवन में अस्थायी स्टॉल हेतु स्थल उपलब्ध कराया। जनपद स्तरीय बागनाथ सहकारिता ने जिम्मेदारी लेते हुए उत्पाद की बिक्री की शुरूआत की। वर्तमान में महादेव स्वायत्त सहकारिता इस कार्य को कर रही है। इस अभिनव प्रयास के अन्तर्गत वर्तमान तक सहकारिता का कुल ₹ 45,445/- का टर्नओवर रहा है।

सहकारिताओं को मिल रहे समर्थन, आय में अतिरिक्त लाभ तथा उपभोक्ताओं तक सीधी पहुंच से प्रभावित होकर सहकारिताओं ने अपने स्थायी ग्राहक बनाने के इस प्रयास को अन्य स्थानीय बाजारों तक पहुंचाने की योजना बनायी है।

पौध तैयारी से विपणन तक

बनाल पट्टी स्वायत्त सहकारिता, उत्तरकाशी द्वारा पॉलीहाउस में टमाटर की 35 हजार पौध की नर्सरी तैयार कर किसानों को रू० 1 प्रति पौध के हिसाब से बेचा गया है। सहकारिता की टमाटर उत्पादन की इस गतिविधि से 6 ग्रामों के 56 किसान जुड़े हैं जो 2 हैक्टेयर भूमि पर टमाटर उत्पादन कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त सहकारिता ने 10 नाली कृषि भूमि किराये पर लेकर स्वयं भी टमाटर उत्पादन आरम्भ किया है। सहकारिता ने उत्पादित टमाटर का विपणन माह जुलाई 2014 से आरम्भ कर दिया है, अगस्त 2014 तक 7896 किग्रा० टमाटर का विपणन किया जिससे सहकारिता का टर्नओवर ₹ 1.67 लाख हुआ है।

जनपद अल्मोड़ा, उत्तरकाशी व चमोली की फेडरेशनों द्वारा प्रथम बार 946 कुं० आलू का विपणन देहरादून व हल्द्वानी मंडी में किया गया। इसके सापेक्ष फेडरेशनों का टर्नओवर ₹ 10.25 लाख रहा।

नई सोच में खोज

परियोजना द्वारा समर्थित कमस्यार घाटी स्वायत्त सहकारिता, खातीगांव, जनपद बागेश्वर में वर्ष 2008 से 20 ग्रामों में कार्यरत है। सहकारिता से 454 सदस्य जुड़े हैं। सहकारिता विभिन्न व्यवसायिक गतिविधियां संचालित कर रही है जैसे-ट्रांसपोर्ट वाहन, संग्रहित बाजारीकरण, क्रॉयलर पालन, डेयरी, मसाला उत्पादन आदि।

सहकारिता के निदेशक मण्डल ने बैठक में चायपत्ती विपणन की कार्ययोजना तैयार की और टाटा अग्नि चाय का व्यापार आरम्भ किया तथा सहकरिता ने अपने सदस्यों को बाजार से कम मूल्य पर चायपत्ती उपलब्ध कराई।

इस व्यवसाय को माह नवम्बर 2013 से आरम्भ किया गया। सहकारिता ने विगत छः माह मे कुल 1832 किग्रा० चाय का विपणन किया। इस व्यवसाय से सहकारिता का फरवरी 2014 तक कुल ₹ 2,27,760 का टर्नओवर हुआ है।

सहकारिता ने सदस्यों की मांग एवं स्थानीय रिटेलर के साथ सर्वे कर समझा कि छोटे पैकेट, जिसका मूल्य ₹ 10 है, की मांग अधिक है। इसी आधार पर सहकारिता ने भविष्य में विपणन की योजना बनाई है। वर्तमान में कमस्यार घाटी सहकारिता जनपद की अन्य सहकारिताओं के साथ मिलकर व्यवसाय का विस्तार कर रही है।

किसानों को मिला नया बाजार

परियोजना के सहयोग से सहकारिताओं ने स्थानीय उत्पादों का संग्रहित बाजारीकण प्रारम्भ किया है, जिससे किसानों को उत्पादों का उचित मूल्य प्राप्त हो सके। जनपद चमोली में संग्रहित बाजारीकरण का कार्य सहकारिताएं संगठित होकर कर रही हैं। इस प्रयास में मां अनुसूया, नंदाकिनी, हरिकुल एवं रूपकुण्ड SRC द्वारा क्रमशः रामदाना, सोयाबीन एवं मंडुवे का संग्रहित बाजारीकरण किया जा रहा है। संग्रहित बाजारीकरण के इस प्रयास में क्षेत्र में गठित अन्य सहकारिताओं की मदद ली जा रही है।

वर्ष 2013 में मां अनुसूया, नन्दाकिनी, हरिकुल एवं रूपकुण्ड SRC द्वारा कुल 25 कुं० मंडुवा, 136 कुं० रामदाना एवं 130 कुं० सोयाबीन का संग्रहण एवं विपणन किया गया।

संग्रहित बाजारीकरण गतिविधि की इस अनूठी पहल से स्थानीय उत्पादों की उचित मूल्य पर खरीद द्वारा व्यापारियों, बिचौलियों/मध्यस्थों एवं सहकारितायों के मध्य एक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हुई है। इस प्रतिस्पर्धा में अंततः किसानों को लाभ प्राप्त हो रहा है। किसानों को पिछले वर्ष की तुलना में 30 से 40 प्रतिशत तक अधिक मूल्य मिला है।

हैंडलूम से बनी पहचान

प्राथमिक साधन सहकारी समिति, ध्याड़ी अल्मोड़ा द्वारा आजीविका परियोजना के अन्तर्गत समूहों का गठन किया गया एवं हैण्डलूम से संबंधित कार्य को आजीविका संवर्धन की एक गतिविधि के रूप में अपनाने हेतु प्रेरित किया गया। परियोजना ने प्रशिक्षण, उपकरण एवं कच्चा माल तथा तैयार उत्पाद के विपणन हेतु सहयोग दिया। इस कार्य से जुड़े सदस्यों को 'देव महिमा उत्पादक समूह' के रूप में संगठित किया गया। समूह में 20 सदस्य हैं, जिन्हें प्रत्यक्ष रूप से एवं 26 अन्य को अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार से मिल रहा है। वर्तमान में समूह को वित्तीय एवं तकनीकी सहयोग हेतु नारी एकता स्वायत्त सहकारिता, भैंसियाछाना से सम्बद्ध किया गया है।

समूह कंबल, शॉल, जुराब, टोपी, थुलमा, पंखी आदि उत्पाद तैयार कर स्थानीय, राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाले मेलों, प्रदर्शनियों में विक्रय करता है। हैण्डलूम उत्पादों की सीमित मांग होने के कारण समूह ने हैण्डलूम के साथ-साथ रेडीमेड ऊनी उत्पाद का विपणन भी शुरू किया है। मार्च 2014 तक समूह का टर्नओवर ₹ 2.60 लाख का हुआ।

ऊनी उत्पाद के विपणन हेतु समूह की योजना जनपद में अन्य सहकारिताओं के साथ मिलकर कार्य करने की है। इस हेतु देव महिमा उत्पादक समूह ने नोडल संस्था के रूप में कार्य आरम्भ कर दिया है।

ग्रेडिंग का लाभ

उपरीकोट गांव विकासखण्ड डुण्डा, जनपद उत्तरकाशी में है। परियोजनान्तर्गत यहां 7 स्वयं सहायता समूह गठित हैं जिनसे 50 सदस्य जुड़े हैं। गांव में मुख्य रूप से आलू का उत्पादन किया जाता है। आलू का विपणन पूर्ण रूप से बिचौलियों पर ही निर्भर है। बिचौलिये आलू का मूल्य 5 से 7 रू० प्रति किग्रा० से अधिक नहीं देते। बाजार तक पहुंच न होने के कारण किसान इस भाव से संतुष्ट रहते हैं।

क्लस्टर में गठित विश्वनाथ स्वायत्त सहकारिता ने पहल करते हुए सर्वप्रथम किसानों को ग्रेडिंग के लाभ के बारे में जानकारी प्रदान की। मंडी में भेजने से पहले समस्त उत्पाद की ए, बी, सी, ग्रेडिंग की गई। सहकारिता द्वारा कुल 154 कुं० आलू देहरादून मंडी में भेजा गया। परिणास्वरूप उत्पादकों को समस्त व्यय जैसे- ट्रांसपोर्ट, मंडी कमीशन आदि की कटौती के उपरानत औसत ₹ 11/- किग्रा० का भाव प्राप्त हुआ

उपरीकोट के किसान इस लाभ से काफी उत्साहित हुए हैं। बाजार एवं ग्रेडिंग की जानकारी के साथ किसान अब बिचौलियों को भी प्रतिस्पर्धी मूल्य में आलू दे रहे है। इस व्यवसाय से अक्टूबर 2013 सहकारिता का ₹ 1,77,736/- का टर्न ओवर हुआ।

आलू बीज से सहकारिता में जगी आशा

बालगंगा स्वायत्त सहकारिता, खिरबेल जनपद टिहरी के भिलंगना विकासखण्ड में कार्य कर रही है। सहकारिता से 15 ग्रामों के 71 स्वयं सहायता समूह एवं 724 शेयरधारक जुड़े हैं। स्वयं के स्वावलम्बन हेतु सहकारिता को व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करना आवश्यक है तथा यह एक चुनौतीपूर्ण कार्य है। सहकारिता ने चुनौती को समझा और इस दिशा में प्रयास आरम्भ किया।

सितम्बर 2013 में सहकारिता ने आलू बीज की मांग का अध्ययन कर पाया कि क्षेत्र में आलू की स्थानीय प्रजाति गंगी की मांग अधिक है तथा किसानों को यह बीज उपलब्ध नहीं हो पाता। सहकारिता ने गंगी क्षेत्र से 33 कुं० बीज क्रय कर किसानों को उपलब्ध कराया। किसानों को बीज 3-5 रूपये प्रति किग्रा० कम कीमत पर, सरलता से तथा समय पर उपलब्ध हो पाया। आलू विपणन से सहकारिता का माह दिसम्बर 2013 में ₹ 1,01,100/- का टर्न ओवर हुआ है।

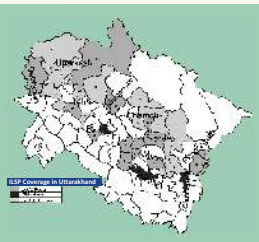

प्रभागीय परियोजना प्रबनधन इकाई सम्पर्क पताः

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, अल्मोड़ा
टेलीफैक्सः 05962-230910, 230305
ईमेलः dpmalmora@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, बागेश्वर
टेलीफैक्सः 05963-221502, 211746
ईमेलः dpmbageshwar@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, चमोली
टेलीफैक्सः 01372-251355, 251451
ईमेलः dpmchamoli@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, टिहरी
टेलीफैक्सः 01376-256133, 256249
ईमेलः dpmtehri@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, उत्तरकाशी
टेलीफैक्सः 01373-223925, 223466
ईमेलः dpmuttarkashi@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, रूद्रप्रयाग
ईमेलः dpmrudraprayag@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, पिथौरागढ़
ईमेलः dpmpithoragarh@ugvs.org

प्रभागीय परियोजना प्रबन्धन इकाई, देहरादून
ईमेलः dpmdehradun@ugvs.org

उत्तराखण्ड ग्राम्य विकास समिति एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना

परियोजना का उद्देश्य उत्तराखण्ड के पर्वतीय जनपदों में गरीबी को कम करना है। ग्रामीण परिवारों को चिरन्तर आजीविका का अवसर उपलब्ध कराने हेतु सक्षम बनाते हुये, उन्हें बाजार अर्थव्यवस्था के साथ जोड़कर इस उद्देश्य की प्राप्ति जानी है।

परियोजना वर्ष 2012-13 से वर्ष 2018-19 तक कुल सात वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत है, जिसका क्रियान्वयन 01 जुलाई 2013 से प्रारम्भ हुआ है। परियोजना का क्रियान्वयन उत्तराखण्ड के 11 जनपदों के 41 विकासखण्डों में किया जा रहा है।

प्रकाशकः श्री विजय कुमार, परियोजना निदेशक, UGVS एवं प्रबन्ध निदेशक UPASaC

संपादकीय टीमः परियोजना स्टाफ

पताः
216, फेज II, पंडितवाड़ी, देहरादून
टेलीफैक्सः 0135-2774800, 2773800
ईमेलः info@ugvs.org
वेबसाईटः www.ugvs.org

केवल सीमित वितरण हेतु प्रकाशित

परियोजना के अन्तर्गत फेडरेशनों की उपलब्धि एक दृष्टि में:

एकीकृत आजीविका सहयोग परियोजना द्वारा ULIPH के अन्तर्गत अल्मोड़ा, बागेश्वर, चमोली, टिहरी एवं उत्तरकाशी जनपदों गठित 53 फेडरेशनों को सहयोग दिया जा रहा है। यह सभी फेडरेशन विभिन्न क्षेत्रों जैसे- शेयरधारक की संख्या में वृद्धि, शेयर धारकों को विभिन्न प्रकार की सामाजिक व आर्थिक गतिविधियों से जोड़ने एवं सेवाएं प्रदान करने आदि में अग्रसर हैं। फेडरेशन सामाजिक विकास के साथ-साथ आर्थिक विकास में भी पहल कर चुकी हैं। इनके द्वारा किये गये प्रयास सराहनीय हैं। अगस्त 2014 तक फेडरेशनों की मुख्य प्रगति का विवरण निम्नानुसार है:

फेडरेशन से जुड़े सदस्य-	31,527
गतिविधियों से जुड़े परिवार-	40,460
कुल व्यवसायिक टर्नओवर-	5.80 करोड़
कुल अर्जित लाभ-	39.45 लाख
फेडरेशन निवेश-	3.94 करोड़

परियोजना के जैविक उत्पादों को जल्द मिलेगा प्रमाणीकरण:

पूर्व में ULIPH परियोजना में जैविक खेती कार्यक्रम 4 परियोजना जनपदों- चमोली, उत्तरकाशी, बागेश्वर, टिहरी के 201 गाँवों में आरम्भ किया गया जिसके अन्तर्गत 34 जैविक किसान समूहों में 9927 किसान 2911 हैक्टेयर भूमि के साथ जैविक खेती एवं जैविक प्रामाणीकरण की प्रक्रिया प्रारम्भ की गई। परियोजना अन्तर्गत उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद के सहयोग से जैविक प्रामाणीकरण हेतु गुणवत्ता प्रकोष्ठ बनाया गया।

चूंकि प्रमाणीकरण प्रक्रिया में 3 वर्ष का समय लगता है। परियोजना के द्वितीय चरण में ऐसे जैविक उत्पादक समूहों, जिनके पास विपणन योग्य उत्पाद का मूल्य रूपये 10 लाख से अधिक हो, को जैविक प्रमाणीकरण हेतु चयनित किया गया। 34 जैविक उत्पादक समूहों में से जनपद उत्तरकाशी एवं चमोली के 7 जैविक उत्पाद समूहों (43 ग्राम, 1920 किसान) की 829 हैक्टेयर भूमि में जैविक खेती एवं जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया जारी है। 4 जैविक उत्पादक समूहों का वर्ष 2014-15 के लिए नवीनीकरण एवं स्कोप प्रमाण पत्र USOCA के माध्यम से APEDA द्वारा निर्गत हो चुका है। इस प्रकार 1480 किसान 3 वर्ष की जैविक प्रमाणीकरण प्रक्रिया पूर्ण कर भारत सरकार द्वारा प्रमाणित जैविक उत्पादकों की श्रेणी में पंजीकृत माने जायेंगे एवं NPOP की मुहर पाने के हकदार होंगे। शेष 27 जैविक उत्पादक समूहों के साथ परियोजना द्वारा प्रमाणीकरण हेतु पारस्परिक गारन्टी सिस्टम आरम्भ किया जा रहा है।

जैविक किसानों को समय-समय पर आवश्यक तकनीकी सहयोग प्रदान करने, बाजार उपलब्ध कराने तथा जैविक खेती कार्यक्रम को आगे बढ़ाने हेतु उक्त जैविक खेती कार्यक्रम को उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद के साथ जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है।

खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि घटक के अन्तर्गत Innovation linkages :

परियोजना के खाद्य सुरक्षा एवं आजीविका वृद्धि घटक में Innovation Linkages के अन्तर्गत विभिन्न अनुसंधान एवं विकास संस्थाओं के माध्यम से परियोजना क्षेत्र में कृषि व पशुपालन को सतत् उद्यम के रूप में स्थापित करने के उद्देश्य से फसल व पशुधन उत्पादकता में वृद्धि करना, उत्पादन लागत में कमी लाना व नयी सम्भावनाओं की तलाश करने हेतु निम्न कार्य किये जाने प्रस्तावित हैं-

- **उत्तराखण्ड जैविक उत्पाद परिषद** के माध्यम से ILSP द्वारा तैयार 07 जैविक उत्पादक समूहों के उत्पादों हेतु भविष्य में आन्तरिक नियंत्रण प्रणाली अपनाते हुए उत्पादों का प्रमाणीकरण कर उत्पादों का सतत् बेहतर मूल्य उपलब्ध करवाना।
- **उत्तराखण्ड पशुधन विकास परिषद (ULDB)** के माध्यम से नये समन्वित पशु विकास केन्द्र की स्थापना करना, जिनके द्वारा पशुओं की नस्ल सुधार, प्राथमिक चिकित्सा, बधियाकरण, दवापान, पशु उपचार सेवाएं उपलब्ध कराना। पुराने समन्वित पशु विकास केन्द्रों के सतत् संचालन हेतु सहयोग प्रदान करना।
- उत्तराखण्ड भेड़ एवं ऊन विकास परिषद (USWDB) के माध्यम से भेड़ एवं भेड़ पालकों का स्वास्थ्य प्रबंधन, आय संवर्धन, ऊन की गुणवत्ता में सुधार, भेड़ों के वजन में बढ़ोत्तरी, बाजार संयोजन आदि कार्यों का निष्पादन।
- **उत्तराखण्ड बांस एवं रेशा विकास परिषद** के माध्यम से बिच्छू घास एवं रिंगाल आधारित उद्यमों की स्थापना कर ग्रामीणों की आजीविका सुधार तथा सतत् विपणन संयोजन आदि कार्यों का निष्पादन।
- **पंतनगर विश्वविद्यालय** के माध्यम से सब्जी उत्पादन, मसालों व बेमौसमी सब्जी की वैज्ञानिक खेती को बढ़ाया देते हुए किसानों को Volume Production हेतु बढ़ावा देते हुए उत्तरोत्तर आय वृद्धि अवसर सृजित करना।
- **कृषि विज्ञान केन्द्र, पिथौरागढ़** के माध्यम से उद्यानिकी व सब्जी उत्पादन कार्यक्रम को बढ़ावा दिया जायेगा, जिसके अन्तर्गत उन्नत तकनीक व उन्नत किस्म के पौधों व बीजों की उपलब्धता किसानों के लिए सुनिश्चित करना।
- **हर्बल रिसर्च विकास संस्थान (HRDI),** गोपेश्वर के माध्यम से जड़ी-बूटी आधारित उद्यमों की स्थापना करना।